

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am aware that the Supreme Court has said that undue delay could become a ground for commutation. The point I am trying to make is that I cannot now explain or wish away the delay that happened between 1998 and 2004 and also the delay which happened between 2004 and November, 2008. Those are cases. ...*(Interruptions)*... Please listen to me. I know, it is embarrassing but please listen to me.

These cases have not been delayed in the Ministry of Home Affairs. As I said, these cases were submitted. Once 14 cases were submitted, and, then, 14 plus 14, were resubmitted, but there was no decision except in two cases, which were resubmitted between 2004 and 2008. Now, we have decided to resubmit the cases once again with a request that a decision be made as early as possible. And, since May 2009, we have resubmitted 13 cases, and, I have obtained a decision in seven cases. There is no delay in the Ministry of Home Affairs but I cannot comment on the time taken by the hon. President of India.

#### नगरीय स्थानीय निकाय प्रशासन हेतु अवसंरचनात्मक सहयोग

\*22. श्री भगत सिंह कोश्यारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय प्रशासन को मजबूती प्रदान करने हेतु वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत अवसंरचनात्मक सहयोग देने के उद्देश्य से कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस मद के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) और लघु तथा मध्यम नगरों का शहरी अवसंरचना विकास (डी.एस.एम.टी.) योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु पात्र नगरीय स्थानीय निकायों के चयन का मानदण्ड क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

#### विवरण

(क) और (ख) शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना राज्य का विषय है। भारत सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी संस्थागत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों में मदद करती है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में चलाई जा रही महत्वपूर्ण स्कीमों के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं:

(i) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन घटक : पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

- (ii) छोटे और मझोले नगरों के लिए शहरी बुनियादी सुविधा विकास संबंधी स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी): पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)
- (iii) सात मेगा शहरों के आस-पास के उप नगरों हेतु शहरी बुनियादी सुविधा विकास संबंधी स्कीम : उक्त स्कीम जुलाई, 2009 में प्रारम्भ की गई थी। इस स्कीम के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई।
- (iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी): इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना राज्यों को निम्नलिखित धनराशि जारी की गई:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
अगरतला (त्रिपुरा)	शून्य	0.11	3.90
आइजोल (मिजोरम)	शून्य	0.72	6.00
गंगटोक	शून्य	शून्य	3.00
कोहिमा (नागालैंड)	शून्य	0.07	5.00
शिलाँग	शून्य	शून्य	4.00
कुल	शून्य	0.90	21.90

- (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए 10% एक मुश्त प्रावधान: पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
अरुणाचल प्रदेश	64.46	16.03	28.56
असम	26.90	9.40	17.82
मणिपुर	6.86	20.92	12.82
मेघालय	3.37	5.09	10.55
मिजोरम	37.55	28.08	17.04
नागालैंड	35.85	32.84	19.60
सिक्किम	54.19	34.59	15.18
त्रिपुरा	40.82	17.65	21.99
कुल	270.00	164.60	143.56

- (vi) शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता निर्माण संबंधी : इस स्कीम के तहत जारी धनराशि निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
उड़ीसा	0.00	0.00	105.09
केरल	0.00	6.53	331.05
कर्नाटक	0.00	0.00	5.51
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	15
छत्तीसगढ़ (1)	0.00	0.00	0
छत्तीसगढ़ (2)	0.00	0.00	265.6
बिहार	6.38	0.00	0.00
गुजरात	11.72	0.00	0.00
कुल	18.10	6.53	752.24

(ग) वर्ष 2001 की जनगणना, राज्य-राजधानियों और धार्मिक:ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य शहरों/शहरी समूहों के आधार पर 65 शहरों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन घटक में शामिल किया गया है। शहरी अवस्थापना और शासन घटक के तहत शामिल नहीं किए गए अन्य सभी नगर छोटे और मझौले नगरों के लिए शहरी बुनियादी सुविधा विकास संबंधी स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत सहायता के पात्र हैं।

**विवरण- I**

पिछले तीन वर्षों के दौरान (जे एन एन यू आर एम) स्कीम के तहत जारी धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि (एसीए)		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	48916.54	18898.95	24885.07
2	अरुणाचल प्रदेश	2006.94	2053.91	2006.94
3	असम	791.26	6321.15	7112.41

1	2	3	4	5
4	बिहार	461.93	1955.62	7441.39
5	छत्तीसगढ़	1272.80	0.00	12145.60
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	24563.54	47035.34	47788.21
8	हरियाणा	1339.84	9147.46	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2619.01
10	जम्मू तथा कश्मीर	6877.36	2500.00	0.00
11	झारखंड	0.00	6682.46	5384.66
12	कर्नाटक	18766.61	12992.94	21578.53
13	केरल	6319.93	3350.50	2439.45
14	मध्य प्रदेश	7914.35	15931.43	12343.27
15	महाराष्ट्र	56827.52	88349.54	88649.86
16	मणिपुर	580.66	0.00	2883.37
17	मेघालय	0.00	4904.04	0.00
18	मिजोरम	378.41	0.00	756.82
19	नागालैंड	179.00	389.26	1702.81
20	उड़ीसा	9978.37	3338.00	2491.60
21	पंजाब	4145.29	4939.22	3346.62
22	राजस्थान	10654.03	20281.38	2826.10
23	सिक्किम	538.20	538.20	1663.87
24	तमिलनाडु	16093.02	26586.11	37723.44
25	त्रिपुरा	0.00	1760.85	2250.00
26	उत्तर प्रदेश	21365.55	43078.75	47632.21

1	2	3	4	5
27	उत्तराखंड	1523.85	2678.56	7546.69
28	पश्चिमी बंगाल	5687.25	22857.17	27717.88
29	दिल्ली	0.00	2220.58	17248.00
30	पुडुचेरी	4068.00	993.20	0.00
31	चंडीगढ़	1544.92	405.20	0.00
	कुल	252795.17	350189.82	390183.81

**विवरण-11**

पिछले तीन वर्षों के दौरान (यूआईडीएसएसएमटी) स्कीम के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि (एसीए)		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	23546.05	75586.14	476.88
2	असम	1645.22	6946.79	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1771.19	0.00
4	बिहार	2689.06	4342.50	0.00
5	छत्तीसगढ़	4289.00	0.00	0.00
6	दादर नगर हवेली	0.00	26.00	719.89
7	दमन एवं द्वीव	0.00	31.00	0.00
8	गुजरात	2678.67	12169.72	0.00
9	गोवा	0.00	0.00	0.00
10	हरियाणा	4190.00	2524.58	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	392.12	85.59	0.00
12	झारखंड	4003.32	0.00	0.00

1	2	3	4	5
13	जम्मू तथा कश्मीर	2724.25	1508.92	0.00
14	केरल	5194.27	8783.42	0.00
15	कर्नाटक	6091.10	14891.23	0.00
16	मध्य प्रदेश	10864.06	12973.95	0.00
17	महाराष्ट्र	10174.78	88262.02	14072.30
18	मणिपुर	644.49	2200.95	0.00
19	मेघालय	0.00	644.97	0.00
20	मिजोरम	0.00	699.77	0.00
21	नागालैंड	0.00	0.00	190.75
22	उड़ीसा	2435.04	4410.38	0.00
23	पंजाब	7587.04	8367.20	0.00
24	पुडुचेरी	0.00	0.00	1567.20
25	राजस्थान	3555.94	19181.70	0.00
26	सिक्किम	735.08	1085.40	0.00
27	त्रिपुरा	2005.00	1577.38	0.00
28	तमिलनाडु	10493.39	29231.75	1935.35
29	उत्तर प्रदेश	10340.11	16865.73	10918.80
30	उत्तराखंड	0.00	2469.3	0.00
31	पश्चिमी बंगाल	4122.00	11388.41	0.00
	कुल	120400.01	328025.99	29880.00

**Infrastructural support for urban local body administrations**

† \*22. SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the schemes of Central Government being run with the aim of providing financial, technical and institutional infrastructural support for strengthening urban local body administrations;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) the details of State-wise and scheme-wise financial assistance given under this head during the last three years; and

(c) the criteria for selection of eligible urban local bodies for providing benefits under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b) Strengthening of Urban Local Bodies is basically a State Subject. Government of India supplements their efforts by providing financial, technical and institutional infrastructural support for strengthening urban local body administrations. Details of the important schemes operated by Government of India in this regard are as follows:

(i) Urban Infrastructure and Governance (UIG) component of Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM):- The year wise details in respect of amount released for the last three years are given in the Statement-I (*See below*).

(ii) Urban Infrastructure Development Scheme for Small And Medium Towns (UIDSSMT):- The year wise details in respect of amount released for the last three years are given in the Statement-II (*See below*).

(iii) Urban Infrastructure Development Scheme for satellite towns around seven mega cities:-

The Satellite Towns scheme was launched in July, 2009 and the fund released under this Scheme during 2009-10 is Rs.5.00 crore for Uttar Pradesh.

(iv) North Eastern Region Urban Development Programme (NERUDP)

Under NERUDP following amounts were released to the project States during last three years:-

(Rs. in crore)

States	2007-08	2008-09	2009-10
Agartala (Tripura)	Nil	0.11	3.90
Aizwal (Mizoram)	Nil	0.72	6.00
Gangtok	Nil	Nil	3.00
Kohima (Nagaland)	Nil	0.07	5.00
Shillong	Nil	Nil	4.00
Total	Nil	0.90	21.90

(v) 10% Lump Sum Provision for the benefit of North Eastern Region:-

Year-wise funds released for the last three years is as under:-

(Rs. in Crore)

States	2007-08	2008-09	2009-10
Arunachal Pradesh	64.46	16.03	28.56
Assam	26.90	9.40	17.82
Manipur	6.86	20.92	12.82
Meghalaya	3.37	5.09	10.55
Mizoram	37.55	28.08	17.04
Nagaland	35.85	32.84	19.60
Sikkim	54.19	34.59	15.18
Tripura	40.82	17.65	21.99
Total	270.00	164.60	143.56

(vi) Capacity Building Scheme for Urban Local Bodies (CBULB):- Funds released under this scheme are shown in the table below:-

(Rs. in lakhs)

States	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
Orissa	0.00	0.00	105.09
Kerala	0.00	6.53	331.05
Karnataka	0.00	0.00	5.51
Madhya Pradesh	0.00	0.00	15



1	2	3	4
Chhattisgarh (1)	0.00	0.00	0
Chhattisgarh (2)	0.00	0.00	265.6
Bihar	6.38	0.00	0.00
Gujarat	11.72	0.00	0.00
Total	18.10	6.53	752.24

(c) 65 Cities, on the basis of population as per census 2001, and State Capitals and other cities/Urban Agglomeration (UAs) of religious/historic and touristic importance have been included in Urban Infrastructure and Governance (UIG) component of JNNURM. All other towns which have not been included under UIG are eligible for assistance under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT).

**Statement-I**

*Year-wise details of amount released under JNNURM Scheme for the last three years*

(Rs. in lakhs)

S.No.	Name of State/UT	Amount of Additional Central Assistance (ACA) released		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1	Andhra Pradesh	48916.54	18898.95	24885.07
2	Arunachal Pradesh	2006.94	2053.91	2006.94
3	Assam	791.26	6321.15	7112.41
4	Bihar	461.93	1955.62	7441.39
5	Chattisgarh	1272.80	0.00	12145.60
6	Goa	0.00	0.00	0.00
7	Gujarat	24563.54	47035.34	47788.21
8	Haryana	1339.84	9147.46	0.00

1	2	3	4	5
9	Himachal Pradesh	0.00	0.00	2619.01
10	Jammu & Kashmir	6877.36	2500.00	0.00
11	Jharkhand	0.00	6682.46	5384.66
12	Karnataka	18766.61	12992.94	21578.53
13	Kerala	6319.93	3350.50	2439.45
14	Madhya Pradesh	7914.35	15931.43	12343.27
15	Maharashtra	56827.52	88349.54	88649.86
16	Manipur	580.66	0.00	2883.37
17	Meghalaya	0.00	4904.04	0.00
18	Mizoram	378.41	0.00	756.82
19	Nagaland	179.00	389.26	1702.81
20	Orissa	9978.37	3338.00	2491.60
21	Punjab	4145.29	4939.22	3346.62
22	Rajasthan	10654.03	20281.38	2826.10
23	Sikkim	538.20	538.20	1663.87
24	Tamil Nadu	16093.02	26586.11	37723.44
25	Tripura	0.00	1760.85	2250.00
26	Uttar Pradesh	21365.55	43078.75	47632.21
27	Uttarakhand	1523.85	2678.56	7546.69
28	West Bengal	5687.25	22857.17	27717.88
29	Delhi	0.00	2220.58	17248.00
30	Puducherry	4068.00	993.20	0.00
31	Chandigarh	1544.92	405.20	0.00
TOTAL		252795.17	350189.82	390183.81

**Statement-II**

*Year-wise details of amount released under UIDSSMT Scheme  
for the last three years*

(Rs. in lakhs)

S.No.	State	Amount of Additional Central Assistance (ACA) released		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1	Andhra Pradesh	23546.05	75586.14	476.88
2	Assam	1645.22	6946.79	0.00
3	Arunachal Pradesh	0.00	1771.19	0.00
4	Bihar	2689.06	4342.50	0.00
5	Chattisgarh	4289.00	0.00	0.00
6	Dadra & Nagar Haveli	0.00	26.00	719.89
7	Daman & Diu	0.00	31.00	0.00
8	Gujarat	2678.67	12169.72	0.00
9	Goa	0.00	0.00	0.00
10	Haryana	4190.00	2524.58	0.00
11	Himachal Pradesh	392.12	85.59	0.00
12	Jharkhand	4003.32	0.00	0.00
13	Jammu & Kashmir	2724.25	1508.92	0.00
14	Kerala	5194.27	8783.42	0.00
15	Karnataka	6091.10	14891.23	0.00
16	Madhya Pradesh	10864.06	12973.95	0.00
17	Maharashtra	10174.78	88262.02	14072.30
18	Manipur	644.49	2200.95	0.00
19	Meghalaya	0.00	644.97	0.00

1	2	3	4	5
20	Mizoram	0.00	699.77	0.00
21	Nagaland	0.00	0.00	190.75
22	Orissa	2435.04	4410.38	0.00
23	Punjab	7587.04	8367.20	0.00
24	Puducherry	0.00	0.00	1567.20
25	Rajasthan	3555.94	19181.70	0.00
26	Sikkim	735.08	1085.40	0.00
27	Tripura	2005.00	1577.38	0.00
28	Tamil Nadu	10493.39	29231.75	1935.35
29	Uttar Pradesh	10340.11	16865.73	10918.80
30	Uttrakhand	0.00	2469.3	0.00
31	West Bengal	4122.00	11388.41	0.00
TOTAL		120400.01	328025.99	29880.00

**श्री भगत सिंह कोश्यारी :** सभापति महोदय, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां समान हैं। ये सभी राज्य विशेष श्रेणी के राज्य हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में JNNURM एवं UIDSSMT के चयनित स्थानीय निकायों को भी स्वयं के द्वारा एकत्र 10 प्रतिशत के योगदान की अनिवार्यता से मुक्त करेंगे? मान्यवर, उन राज्यों में 10 प्रतिशत योगदान नहीं दिया जाता है। केवल दो राज्यों में, जो गरीब राज्य हैं, उनके गरीब निकायों को यह 10 प्रतिशत मिल सकता है। क्या आप वहां के स्थानीय निकायों को भी 10 प्रतिशत की अनिवार्यता से मुक्त करेंगे?

**श्री कमल नाथ :** सर, यह जो योजना है, इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं और 12वें प्लान में इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार इसमें संशोधन किया जाए। पिछले छः सालों में इसमें हमें जो एक्सपीरिंस प्राप्त हुआ है, उसका लाभ उठाते हुए इस पर अवश्य विचार किया जाएगा कि कौन से राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जाए।

**श्री भगत सिंह कोश्यारी :** मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बारहवीं योजना के लिए हम नये प्रकार से सोच-विचार करेंगे, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ हिमालय क्षेत्र वन बहुल क्षेत्र है। लोगों के रहने लायक जमीन यहां बहुत कम है,

लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए पहाड़ों में भी छोटे-छोटे नये कस्बों का उदय हो रहा है। आप जानते हैं कि पर्यटन के लिहाज से और धार्मिक लिहाज से भी वहां बहुत से लोग जाते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप नयी योजनाएं बनाएंगे, तो JNNURM के अंतर्गत क्या छोटी-छोटी जगहों पर कुछ नये आदर्श शहर बनाने के लिए आप कोई विशेष योजना बनाएंगे? इससे पहाड़ के लोग पलायन भी नहीं करेंगे और वहां के जो छोटे-छोटे गांव हैं, वहां नये आदर्श शहर स्थापित हो सकेंगे। क्या आप इस योजना के अंतर्गत उनके लिए विचार करेंगे?

**श्री कमल नाथ :** सर, हम इन सब चीजों के बारे में विचार करेंगे क्योंकि अब हमें इसमें छः साल का एक्सपीरिंस भी प्राप्त हो गया है। नॉर्थ-ईस्ट अपनी जगह है, कश्मीर अपनी जगह है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अपनी जगह हैं। पिछले छः साल में इसमें हमें जो कठिनाइयां आई हैं एवं जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार इस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा। अगर माननीय सदस्य अपने सुझावों को अलग से लिख कर मुझे दे दें, तो हम प्लानिंग कमीशन से चर्चा करके इस योजना को फिर से लागू करने का प्रयास करेंगे।

MS. MABEL REBELLO: Sir, there are two Annexures in the reply given by the hon. Minister and both of them seem to be almost identical. The second Annexure shows that zero assistance was given to the State of Jharkhand during 2008-09. Again, during 2009-10, zero assistance was given to the State of Jharkhand. Sir, you see the figures. They show that developed States are getting more money, more Central assistance than developing States. With this, the gap between the developed States and the developing States is increasing. States like Jharkhand and other poorer States, affected by Left Wing Extremism, are not getting any special assistance from the Central Government. Does the Minister have any intention to help the poorer States so that they come at par with the developed States? Otherwise, there will be tremendous gap between the developed States and the developing States and there will be a lot of problems for the country. What is the Minister planning to do about this?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, what the hon. Member has said is true. In 2007-08, no Central assistance was given to the State of Jharkhand for Urban Infrastructure and Governance. And also ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: He should say why Jharkhand was not given any assistance. ...*(Interruptions)*... What he is saying is mentioned here in the reply. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAUGATA RAY: The Centre does not give assistance on its own. The States have to submit a proposal with a proper detailed project report. If a State does not give a proposal, how can the Centre suo motu, on its own, give any assistance? It is obvious that there was no proposal from Jharkhand in 2007-08 as far as UIG is concerned.

MS. MABEL REBELLO: No, Sir, it is wrong. It is not so. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, ...*(Interruptions)*... You have asked one question. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Jharkhand had submitted a proposal, Sir. ...*(Interruptions)*... It is the duty of the Government to see that poorer States are assisted. What is the meaning of this answer? ...*(Interruptions)*... There is no meaning at all. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If the answer is wrong, please challenge it, but not here. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: She is saying that the Jharkhand Government had submitted a proposal and the Minister is saying that they had not submitted any proposal. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If the answer is wrong, there is a procedure for challenging it. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: The Minister does not want to understand. ...*(Interruptions)*... He does not know the ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: They had submitted a proposal. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Rudyji, please ...*(Interruptions)*... Just one minute. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAMAL NATH: Sir, I appreciate that the hon. Member's concern for the poorer States is as much as mine. Of course, the Government is going to look at States which are the poorer States and the more backward States; not only the poorer States, but also the smaller municipalities and

more backward municipalities and the Nagar Panchayats. It is a fact, Sir, which has been said earlier, that these schemes are not suo motu dealt with by the Central Government. They are proposed by the State Governments.

The State Government has a State-level Committee which first approves it. That State-level Committee sends it to the Central Government. A municipality or a municipal corporation could have made a scheme. But that scheme may not have necessarily been approved by the State-level Committee. Once the State-level Committee approves the scheme, it comes to the Central Government. The Central Government at its level and its Committee approve it. If the hon. Member has any specific scheme, which she feels has not been dealt with by the Centre, I will be happy to receive it and attend to it.

DR. ASHOK S. GANGULY: Hon. Minister, there were reports in the media that the Chief Minister of Arunachal Pradesh had expressed deep distress at the absence of roads and because the Chinese had objected to the Asian Development Bank funding the roads to important border posts. As a consequence, the border posts are not connected to Itanagar. People find it very difficult to communicate, to travel to more sensitive border areas where huge infrastructure is being built by the Chinese. What are the steps being taken in order to provide relief particularly to Arunachal Pradesh?

SHRI KAMAL NATH: Sir, if he had asked me this question two months ago when I was the Minister of Road Transport, I would have been happy to answer it. Nonetheless, I will tell the hon. Member that there is a special scheme for roads and highways in the North-Eastern Region which is being implemented and the President in her Address has also highlighted it.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, for implementing the JNNURM project, land acquisition cost is a major component. But it is not included in the JNNURM project. I would like to know whether the Government has any plan to give provisions for land acquisition cost under the JNNURM.

SHRI SAUGATA RAY: Sir, as the hon. Minister has replied, the JNNURM project was conceived in 2005. From the beginning, it was decided that land acquisition cost would not be given except for the North-Eastern States and Jammu and Kashmir. As the Minister has pointed out, we are having a review of the JNNURM. In the next Plan, maybe a new Mission will come and then,

going by our experience in implementing the JNNURM in the present way, it will be looked into whether the land acquisition cost could be included. But as of now, except for Jammu and Kashmir and the North-Eastern States, there is no provision for giving cost of land.

#### **Increase in interest rate on EPF**

\*23. SHRI R.C. SINGH: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Board of Trustees had decided to increase the rate of interest on EPF from present 8.5 per cent to 9.5 per cent;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Ministry has been able to take up this matter with the Ministry of Finance for a positive decision; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

#### **Statement**

(a) to (d) Yes, Sir. For the financial year 2010-2011, 9.5% rate of interest on EPF has been recommended by the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund [CBT(EPF)] in the 190th meeting held on 15.09.2010 based on the funds available in the interest suspense account. The Ministry of Labour & Employment has forwarded the recommendation of CBT to the Ministry of Finance (Department of Financial Services) for approval.

**श्री आर.सी. सिंह** : सर, मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन्होंने न्यासी बोर्ड के 2009-2010 के डिजीज़न को वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वह इसको कब तक लागू कर पायेंगे? क्योंकि, वर्ष 2010-2011 से इसको लागू करना था और अब यह वर्ष समाप्ति की तरफ जा रहा है। यह ब्याज दर वह कब तक लागू कर पायेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ?

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे** : सर, इसे हमने फाइनांस डिपार्टमेंट को भेजा है। हम pursue कर रहे हैं कि इसको जल्द-से-जल्द अप्रूवल मिले। हम मार्च के अंत तक किसी न किसी हालत में इसकी मंजूरी लेने की पूरी कोशिश करेंगे।